भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2520
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय:- कृषि उपज मंडी

2520. श्री भारत सिंह कुशवाह:
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) इस कृषि उपज मंडियों में खुली नीलामी के आधार पर किसानों की कृषि एवं बागवानी उपजों को बेचने का कोई प्रावधान है;
(ख) क्या छोटे बागवानी किसान अपनी उपज कुषि उपज मंडियों तक लाने में असमर्थ हैं; और
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि एवं बागवानी उपज के विक्रय हेतु अलग-अलग कृषि उपज मंडियां और बागवानी उपज मंडियां बनाने के लिए पायलट परियोजना के रूप में कोई अध्ययन करने का विचार रखती है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): कृषि विपणन राज्य का विषय है। कृषि उपज मंडी समितियां (एपीएमसी) वैधानिक बाजार समितियां हैं, जिनका गठन राज्य सरकारों द्वारा कृषि उपज मंडियों या एपीएमसी में अधिसूचित कृषि या बागवानी उत्पादों के व्यापार को विनियमित करने के लिए किया जाता है, जिन्हें राज्यों में एपीएमसी अधिनियमों के तहत स्थापित किया जाता है।

एपीएमसी में उपज बेचने का सबसे प्रचलित प्रावधान खुली नीलामी के माध्यम से है। चूंकि बागवानी उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए हैंडलिंग घाटे को कम करने के लिए, अधिकांश राज्यों ने मंडियों के साथ-साथ बाजार यार्ड के बाहर भी व्यापार की अनुमति दी है।

(ग): जी नहीं, वर्तमान में कोई अध्ययन कराने का प्रस्ताव नहीं है। राज्यों को राज्य अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार एपीएमसी खोलने और संचालित करने की स्वायत्तता है, जिसमें अनाज, फल और सब्जियों तथा फूलों के लिए अलग-अलग मंडियां शामिल हैं।

*****